फार्मा उद्योग अमेरिकी टैरिफ से बाहर

जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े निर्माता के रूप में भारत की भूमिका बनी कारण, 35% निर्यात को मिली छूट

नई दिल्ली 28 अगस्त इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया के अग्रणी जेनेरिक दवा निर्माता के रूप में भारत का रोल ही ये बता सकता है कि दवा उद्योग को अमेरिकी टैरिफ से बाहर क्यों रखा गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार से भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है. हालांकि, अमेरिका को भारत के फार्मा निर्यात (जो भारत के कुल फार्मा निर्यात का 35 प्रतिशत है) को टैरिफ से बाहर रखा गया है. यह सेक्टर वर्तमान में सेक्शन 232 इनवेस्टिगेशन के तहत रिव्यू में है.

इंडिया का जेनेरिक एक्सपोर्ट- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जेनेरिक निर्यात का लो कॉस्ट और हाई वैल्यू वाला प्रस्ताव अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा उद्योग को महत्वपूर्ण लागत लाभ देता है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में फार्मा रेवेन्यू में अमेरिका के योगदान का अनुपात लगातार घट रहा है. ऐसा कीमतों में गिरावट और मार्जिन व रिटर्न पर इसके प्रभाव के कारण है. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के निदेशक विवेक जैन ने कहा, अधिकांश भारतीय फार्मा कंपनियों का अमेरिकी बाजार में जेनेरिक कारोबार है, जिससे उन्हें कम ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है.

जेनेरिक दवाइयां रख रही हैं टैरिफ को दूर

इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस (एपीए) के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि जेनेरिक दवाओं को इस बहिष्कार का प्रमुख कारण मान सकते हैं, जो अमेरिका में किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. भारत सबसे सस्ती दवाएं प्रदान करता है और विश्व स्तर पर इसका सबसे बड़ा उत्पादक है. देश का फार्मास्युटिकल क्षेत्र दुनिया की लगभग 80 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की सप्लाई करता है.

लगातार दूसरे दिन लुढ़के शेयर बाजार, सेंसेक्स 706 अंक टूटा

मुंबई, 28 अगस्त (वार्ता) अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत और बढ़ने से घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को निवेशक बिकवाली रहे और सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गयी.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 705.97 अंक (0.87 प्रतिशत) लुढ़ककर 80,080.57 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 211.15 अंक यानी 0.85 प्रतिशत टूटकर 24,500.90 अंक पर आ गया.

बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बिकवाली रही. दो दिन में सेंसेक्स 1,555 अंक और निफ्टी-50 467 अंक उतर चुका है.

औद्योगिक विकास चार माह के उच्चतम स्तर पर

जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3.5% बढ़ा
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 5.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज

नई दिल्ली,28 अगस्त.भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित औद्योगिक विकास दर जुलाई में चार महीनों के उच्चतम स्तर 3.5 प्रतिशत पर रही है। इसकी वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मजबूत प्रदर्शन करना था।

यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा गुरुवार को दी गई।इससे पहले देश में औद्योगिक विकास दर जून में 1.5 प्रतिशत रही थी।आंकड़ों के मुताबिक कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने सालाना आधार पर जुलाई में 5.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है।मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ही देश के विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग संस्थानों से निकलने वाले युवा स्नातकों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान करता है।जुलाई में बिजली उत्पादन में मामूली 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, खनन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई और भारी मानसूनी बारिश के कारण उत्पादन में (-) 7.2 प्रतिशत की कमी आई है।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 23 उद्योग समूहों में से 14 ने पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में जुलाई में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।जुलाई में मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल उद्योग समूह में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उद्योग समूह में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर्स, कंट्रोल पैनल और ट्रांसफॉरमर शामिल किए जाते हैं। वहीं, मैन्युफैक्चर ऑफ अदर नॉनमिटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स उद्योग समूह में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

सरकार निर्यात संवर्धन मिशन तेज़ करेगी

मिशन, नए मुक्त व्यापार समझौते और घरेलू बाजार पर ध्यान
निर्यात विविधीकरण से व्यापार की गति बनी रहेगी

नयी दिल्ली, 28 अगस्त. सरकार निर्यातकों की मदद के लिए 'निर्यात संवर्धन मिशन' के क्रियान्वयन में तेजी लाने का प्रयास कर रही है. एक सरकारी अधिकारी ने अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के एक दिन बाद यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्यातकों ने नकदी के मोर्चे पर सरकार से मदद मांगी है और इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है.उन्होंने कहा, ''निर्यात विविधीकरण, नए मुक्त व्यापार समझौते, निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत और बढ़ता घरेलू बाजार, भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क के प्रभाव से बचाने में मदद करेंगे. अधिकारी ने कहा, सरकार निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत है और उनकी मदद के लिए सकारात्मक प्रयास चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि निर्यात के विविधीकरण से निर्यातकों को लंबे समय तक व्यापार की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी. अधिकारी ने प्रस्तावितभारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संबंध में कहा, हमें उम्मीद है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होगी.

अडानी पोर्टफोलियो को 23,793 करोड़ का परिचालन लाभ

अहमदाबाद, 28 अगस्त. अडानी समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 23,793 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हुआ है जो साल-दर-साल 3.3 प्रतिशत अधिक है. अडानी समूह द्वारा गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जून 2025 में समाप्त 12 महीने के दौरान अडानी पोर्टफोलियो ने 90,572 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया जो एक नयी उपलब्धि है. इसमें साल दर साल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अडानी समूह ने पहली तिमाही के मजबूत प्रदर्शन का श्रेय हवाई अड्डा परिचालन जैसे नये कारोबारों के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्युशन्स, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट को दिया है.

हवाई यात्री ट्रैफिक में वृद्धि का अनुमान

वित्त वर्ष 2026 में 17.6 करोड़ तक पहुंच सकता है आंकड़ा

नई दिल्ली, 28 अगस्त. भारतीय हवाई यात्री ट्रैफिक वॉल्यूम के वित्त वर्ष 2026 में 17.2 से 17.6 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4-6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. रेटिंग एजेंसी आईसीआरए द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

यह वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब देश में नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में इजाफा हो रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक की वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लंबे समय तक मानसून और अमेरिकी टैरिफ जैसे कारक हवाई यातायात और व्यापार भावना को प्रभावित कर सकते हैं. आईसीआरए की वरिष्ठ उपाध्यक्ष किंजल शाह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारतीय विमानन उद्योग को हवाई यात्रा की अच्छी मांग के कारण बेहतर मूल्य निर्धारण क्षमता का लाभ मिला था.

आईसीआरए का अनुमान है कि बढ़ती विमान आपूर्ति और यात्री ट्रैफिक वृद्धि में कमी के कारण भारतीय विमानन उद्योग को वित्त वर्ष 2026 में 95-105 अरब रुपए का शुद्ध घाटा हो सकता है. यह घाटा वित्त वर्ष 2025 के 55 अरब रुपए के घाटे से अधिक है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 और 2023 की तुलना में काफी कम है.

भारत-अफ्रीका व्यापार 100 अरब डॉलर के पार : कीर्ति वर्धन

नई दिल्ली, 28 अगस्त. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 20वें सीआईआई इंडिया-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और अफ्रीका के बीच का व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में मात्र 56 अरब डॉलर था.

सिंह ने बताया कि 1996 से 2024 के बीच 75 अरब डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ, भारत अब अफ्रीका में शीर्ष पाँच निवेशकों में शामिल हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अफ्रीका में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12 अरब डॉलर से अधिक का रियायती ऋण और 70 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की है. इसके अलावा, भारत ने अफ्रीकी युवाओं के लिए 50,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं, जिनमें से 42,000 से अधिक का उपयोग किया जा चुका है. मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा. उन्होंने याद दिलाया कि भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता दी गई थी. सिंह ने कहा, हम वैश्विक मंच पर अफ्रीका के उचित स्थान पर जोर देते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत ने मोजाम्बिक, मेडागास्कर और मॉरीशस जैसे देशों में राहत कार्यों के दौरान हमेशा अफ्रीका का साथ दिया है. उन्होंने अफ्रीकी देशों को जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया.

निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित कर रहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घाना का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने विकास सहयोग पर बात की, जो मांग-आधारित है और स्थानीय क्षमता तथा अवसर सृजन पर केंद्रित है. जिम्बाब्वे जैसे अफ्रीकी देश भारतीय कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.

एआई इंजीनियरों की बढ़ रही सैलरी

वरिष्ठ एआई इंजीनियरों को 58-60 लाख रुपये वार्षिक पैकेज.
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई सिक्योरिटी और ऑर्केस्ट्रेशन की

नई दिल्ली, 28 अगस्त. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को तेजी से अपनाने के कारण भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) में जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस जैसी भूमिकाएं सैलरी के नए बेंचमार्क तय कर रही हैं.

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इन नौकरियों में वरिष्ठ कर्मचारियों को सालाना 58-60 लाख रुपये तक का पैकेज मिल रहा है. टीमलीज डिजिटल की रिपोर्ट बताती है कि यह उछाल एआई-नेटिव ऑपरेटिंग मॉडल की ओर बदलाव का संकेत है, जहाँ बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) का एकीकरण और आईपी के नेतृत्व वाले इनोवेशन मानक बन रहे हैं. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम सिक्योरिटी, एआई ऑर्केस्ट्रेशन, और एआई अनुपालन जैसी विशिष्ट एआई कौशलों की मांग विशेष रूप से बीएफएसआई, स्वास्थ्य सेवा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत मजबूत है.

साइबर सुरक्षा और डेटा इंजीनियरिंग जैसी पारंपरिक तकनीकी भूमिकाएं भी जीसीसी में मजबूत बनी हुई हैं. साइबर सुरक्षा पेशेवरों का औसत वेतन वित्त वर्ष 2027 तक 28 लाख

हीरा उद्योग पर टैरिफ का असर

मुंबई, 28 अगस्त (वार्ता) अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर बुधवार से 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लागू होने से भारत में हीरा तराशने के काम में लगे उद्योग के राजस्व में चालू वित्त वर्ष में 28 से 30 प्रतिशत गिरावट आने की आशंका है.

बाजार अध्ययन एवं साख निर्धारण एजेंसी क्रिसिल ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में प्राकृतिक हीरों को तराशने वाले उद्योग का राजस्व 16 अरब डॉलर रहा था, लेकिन अमेरिका में 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगने के बाद अब इसके करीब 30 प्रतिशत घटकर 12.50 अरब डॉलर के आसपास रहने की संभावना है. पहले ही यह उद्योग कीमतों में कमी और अमेरिका तथा चीन में मांग में गिरावट की मार झेल रहा है, जिस कारण पिछले तीन वित्त वर्ष में इसका राजस्व करीब 40 प्रतिशत घट गया है.

अमेरिका ने अगस्त के पहले सप्ताह में भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था. इसके बाद 27 अगस्त से 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया गया है. इस प्रकार कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है.

रूस से तेल आयात का लाभ सिर्फ 2.5 अरब

नयी दिल्ली, 28 अगस्त. रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल आयात करने से भारत को होने वाला वार्षिक शुद्ध लाभ महज 2.5 अरब डॉलर है, जो पहले जताए गए 10 से 25 अरब डॉलर के अनुमान से बहुत कम है. ब्रोकरेज कंपनी सीएलएसए की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रूसी कच्चे तेल के आयात से भारत को होने वाला लाभ मीडिया में बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. हमारे अनुमान के मुताबिक, यह लाभ भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.06 प्रतिशत यानी करीब 2.5 अरब डॉलर है.'

भारत-अफ्रीका व्यापार 100 अरब डॉलर के पार : कीर्ति वर्धन

नई दिल्ली, 28 अगस्त. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 20वें सीआईआई इंडिया-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और अफ्रीका के बीच का व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में मात्र 56 अरब डॉलर था.

सिंह ने बताया कि 1996 से 2024 के बीच 75 अरब डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ, भारत अब अफ्रीका में शीर्ष पाँच निवेशकों में शामिल हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अफ्रीका में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12 अरब डॉलर से अधिक का रियायती ऋण और 70 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की है. इसके अलावा, भारत ने अफ्रीकी युवाओं के लिए 50,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं, जिनमें से 42,000 से अधिक का उपयोग किया जा चुका है. मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा. उन्होंने याद दिलाया कि भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता दी गई थी. सिंह ने कहा, हम वैश्विक मंच पर अफ्रीका के उचित स्थान पर जोर देते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत ने मोजाम्बिक, मेडागास्कर और मॉरीशस जैसे देशों में राहत कार्यों के दौरान हमेशा अफ्रीका का साथ दिया है. उन्होंने अफ्रीकी देशों को जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया.

निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित कर रहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घाना का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने विकास सहयोग पर बात की, जो मांग-आधारित है और स्थानीय क्षमता तथा अवसर सृजन पर केंद्रित है. जिम्बाब्वे जैसे अफ्रीकी देश भारतीय कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.

समाचार विशेष

भाजपा की मिशन 2029 की तैयारी शुरू

चंडीगढ़. हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हारी 42 सीटों पर अगले चुनाव में कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी रणनीति के साथ जुट गई है. मिशन-2029 की तैयारियों को धार देने के लिए हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति तैयार की जा रही है. संगठनात्मक मजबूती, जनता से सीधा संवाद और हारी हुई सीटों पर रणनीति, इन्हीं तीन बिंदुओं पर मिशन-2029 की नींव रखी जा रही है.

भाजपा नेताओं ने गत मंगलवार को चंडीगढ़ और पंचकूला में एक के बाद एक कई बैठकें की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली और संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने अलग-अलग बैठकों की कमान संभाली. प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, डॉ. अर्चना गुप्ता और कृष्ण कुमार बेदी भी इन बैठकों में शामिल हुए.

सबसे पहले सुबह मुख्यमंत्री आवास पर जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों की पहली बैठक हुई. इस बैठक में हाल ही में संपन्न जिला कार्यकारिणी की बैठकों की समीक्षा की गई और संगठन व सरकार के बीच बेहतर तालमेल की रणनीति पर चर्चा हुई. हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री व कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, डॉ. अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि जनता तक सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए, ताकि पार्टी की पकड़ जमीनी स्तर पर और मजबूत हो सके. इसके बाद भाजपा ने उन 42 नेताओं को बुलाया जो 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर हार चुके थे. इनमें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जैसे दिग्गज भी शामिल रहे.

बड़े लक्ष्य को साधने की तैयारी

राजनीतिक हलकों में भाजपा की इन बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है. एक ओर भाजपा अपने घर को दुरुस्त करने में जुटी है तो दूसरी ओर विपक्षी दलों की नजर भी इन बैठकों पर टिकी हुई है. यह स्पष्ट है कि हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में भाजपा अपनी रणनीति और जमीनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए आक्रामक तेवर अपनाएगी. भाजपा की तैयारी बड़े लक्ष्य को साधने की है. विधानसभा चुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशियों की बैठक के बाद पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा. जिन विधानसभा सीटों पर हार हुई हैं, उनमें कोई प्रतिनिधि न रहने के कारण विकास में कमी न आ जाए, इसके लिए बैठक में कार्ययोजना बनाई गई.

74 की उम्र में भी ठोकेंगे ताल

8वीं बार एमएलए बनने की है तैयारी, कोई चुनाव नहीं हारे नरेंद्र नारायण यादव

पटना. नरेंद्र नारायण यादव एक ऐसे नेता हैं जो जेपी आंदोलन से लगातार राजनीति में एक्टिव हैं. मधेपुरा के आलमगंज सीट से लगातार 7वीं बार विधायक रह चुके हैं और आठवीं बार फिर ताल ठोकने को तैयार हैं. खास बात यह है कि वे अपने राजनीतिक करियर में आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं.

74 वर्षीय नरेंद्र नारायण यादव बिहार की राजनीति के उन दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपनी चुनावी जिंदगी में हार देखी ही नहीं. लगातार सात बार आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है. 16 जनवरी 1951 को मधेपुरा जिले के बालाटोल गांव में जन्मे नरेंद्र नारायण यादव छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे. उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन में भी भाग लिया और यहीं से राजनीति की ओर उनका रुझान बढ़ा.

इनकी पढ़ाई लिखाई भी उस समय के हिसाब से काफी अच्छी रही. इन्होंने विज्ञान से ग्रेजुएशन यानी बीएससी की डिग्री ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 1974 में प्राप्त की. 1978 से लेकर 1995 तक नरेंद्र नारायण यादव लगातार प्रखंड प्रमुख रहे. राजनीति में एक लंबी यात्रा के बाद 1995 में पहली बार आलमनगर से विधायक बने और तब से लगातार जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर जीतते आ रहे हैं. इस सीट पर उनकी बादशाहत चलती है.

सरकारी आवास पर 10 कमरे गरीबों के लिए

पटना इलाज करवाने आने वाले कोसी इलाके के गरीब और लाचार बीमार लोगों के लिए नरेंद्र नारायण यादव का सरकारी आवास आश्रय स्थल है. हर रोज यहां 40 से 50 लोग पहुंचते हैं. रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था रहती है. रोगियों को आर्थिक मदद भी करते हैं. बताया जाता है कि नरेंद्र नारायण यादव ने सरकारी आवास पर 10 कमरे गरीबों के लिए रखे हैं. फरवरी 2024 में वे निर्विरोध रूप से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए. इस चुनाव में उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिला. इनकी छवि एक साफ सुथरे और अनुभवी नेता की है.

लेफ्ट को अयप्पा और टीएमसी को मां दुर्गा का सहारा

नई दिल्ली. राजनीति में कमाल की उलटबांसियां देखने को मिलती हैं. ईश्वर को नहीं मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां इन दिनों लॉर्ड अयप्पा के भक्तों के स्वागत की तैयारी में लगी हैं. ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले जब यह आदेश दिया था कि युवा महिलाओं को सबरीमाला में भगवान अयप्पा के मंदिर में जाने से रोकने की प्रथा असंवैधानिक है, तब कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस फैसले का जम कर स्वागत किया था.

हालांकि इसके लिए उनको लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी. लेकिन अब केरल की कम्युनिस्ट सरकार भगवान अयप्पा के भक्तों के एक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रही है. यह वैश्विक सम्मेलन 20 सितंबर को होगा. इसका नाम 'ग्लोबल अयप्पा समागमम' है. सबरीमाला मंदिर के पास पम्बा में इसका आयोजन हो रहा है. पिनरायी विजयन की पूरी सरकार इसको सफल बनाने में लगी है. ध्यान रहे अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव है.

इसी तरह उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इस बार दुर्गापूजा में दिल खोल कर खर्च कर रही है. ममता बनर्जी ने पूजा पंडालों को मिलने वाली मदद की राशि बढ़ा दी है.

अब पूजा पंडालों को 80 हजार रुपए की जगह एक लाख 10 हजार रुपए दिए जाएंगे. अगले महीने होने वाली दुर्गापूजा पर ममता सरकार पांच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसका लाभ हजारों पूजा पंडालों को मिलेगा. ममता बनर्जी ने भाजपा के जय श्रीराम के नारे के मुकाबले जय मां दुर्गा और जय मां काली का नारा चलाया हुआ है. इसके साथ ही जय जगन्नाथ का नारा भी चल रहा है. वैसे पश्चिम बंगाल में भी कम्युनिस्ट नेता दुर्गापूजा को धर्म की बजाय संस्कृति का हिस्सा बता कर पहले ही पंडालों में जाने लगे हैं. इसका मतलब है कि सेकुलर पार्टियों को भी चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा लेने में कोई दिक्कत नहीं है.

विशेष | लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम है शामिल

बिहार चुनाव से पहले भाजपा में होगा बदलाव

नई दिल्ली. बिहार के अंदर इसी साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है. ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टी अपने समीकरण को तैयार करने में लगी हुई है ताकि वह मैदान में किसे उतारे और उससे पार्टी को लाभ पहुंचे और वह सरकार आए.

अब इस बीच खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है. दरअसल,बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी की कई वजहें है. उनमें से इसमें एक बड़ी वजह भाजपा की मातृ संगठन द्वारा नए अध्यक्ष के नाम को लेकर किया गया व्यापक विचार-विमर्श भी है. सूत्रों के मुताबिक,बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के चयन में बीते शाम आरएसएस ने विस्तृत रायशुमारी की है. इसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है.

सूत्रों के अनुसार, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और आरएसएस तथा बीजेपी से जुड़े और संवैधानिक पदों पर रह चुके नेताओं से भी बातचीत की गई है और उनके सुझाव लिए गए है.

आठ राज्यों में चुनाव बाकी

मालूम हो कि, भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसके 36 संगठनात्मक राज्यों में से कम से कम 19 में अध्यक्षों का चुनाव होना आवश्यक है. इनमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. ऐसे में बीजेपी ने जुलाई तक 36 में से 28 संगठनात्मक राज्यों में चुनाव पूरा कर लिया. इसके बाद अब केवल आठ राज्यों में चुनाव बाकी है. ये हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, पंजाब और मणिपुर. हालांकि पंजाब में बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है.